

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 268
जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।
6 अग्रहायण, 1946 (शक)

उत्पाद नवाचार हेतु स्टार्टअप एक्सेलेरेटर

268. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना क्षेत्र में उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर के अपने नेटवर्क को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें और उपाय किए हैं।

उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि (समृद्ध) कार्यक्रम के लिए एमईआईटीवाई के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर को अगस्त 2021 में तीन वर्ष की अवधि (आगे एक वर्ष के लिए विस्तारित) के लिए लॉन्च किया गया था ताकि मौजूदा और आने वाले एक्सेलेरेटर के माध्यम से लगभग 300 स्टार्टअप को गति दी जा सके। वर्तमान में, समृद्ध कार्यक्रम के तहत, भारत के 12 राज्यों में फैले 22 चयनित एक्सेलेरेटर के माध्यम से 175 स्टार्टअप का चयन किया गया है और गति दी गई है।

इसके अलावा, एमईआईटीवाई ने भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स (जेनेसिस)' योजना शुरू की है। इस योजना में पांच वर्ष की अवधि में 490 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का पता लगाने, विकास और वृद्धि करने के लिए लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है और इसे एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास पर केंद्रित निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है:

1. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई): इस पीएलआई योजना के तहत अब तक 9,349 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश किया गया है। इससे 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है।
2. आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना: इस पीएलआई योजना के तहत अब तक 501 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश किया गया है। इससे 10,245 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है।
3. सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है:

- क. भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना, जो भारत में सिलिकॉन पूरक धातु-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (सीएमओएस) आधारित सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए समान आधार पर परियोजना लागत का 50% वित्तीय समर्थन प्रदान करता है।
- ख. भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना, जिसके तहत भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत के 50% के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ग. भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना, जो भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर्स (माइक्रो-इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए समान आधार पर पूंजीगत व्यय का 50 % वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- घ. 'डिजाइन लिंकड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना' के माध्यम से डिजाइन पर प्रोत्साहन प्रदान करना, जो प्रति आवेदन 15 करोड़ रु की सीमा के बशर्ते पात्र व्यय के 50% तक "उत्पाद डिजाइन लिंकड प्रोत्साहन" प्रदान करती है और साथ ही प्रति आवेदन 30 करोड़ रु की सीमा के बशर्ते 5 वर्षों में निवल बिक्री कारोबार के 6% से 4% तक "नियोजित लिंकड प्रोत्साहन" प्रदान करती है।

3.1 सरकार ने कार्यकुशलता और समय चक्र बढ़ाने के लिए सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है।

3.2 देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को और अधिक सहायता देने तथा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सृजित करने के लिए सरकार ने अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

3.3 इसके अलावा, सरकार सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में विश्व स्तरीय प्लेयर्स के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रही है। मेसर्स एप्लाइड मैटेरियल्स इंक. (एएमएटी) ने 4 वर्षों में 400 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ बेंगलुरु में एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके हिस्से के रूप में, एएमएटी द्वारा बेंगलुरु में इंडिया वैलिडेशन सेंटर पहले ही स्थापित किया जा चुका है। यह इंजीनियरिंग केंद्र सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायीकरण पर केंद्रित है।

3.4 भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण में इंजीनियरों के कौशल विकास के लिए एलएएम रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

3.5 मेसर्स एएमडी ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा वैश्विक डिज़ाइन केंद्र, एएमडी टेक्नोस्टार स्थापित किया है। यह केंद्र 3डी स्टैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित सेमीकंडक्टर तकनीक के डिज़ाइन और विकास पर केंद्रित है।

3.6 सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, योजना के परिव्यय का 2.5% तक अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है।

3.7 भारत देश में एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में, भारत पहले से ही सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइनिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर्स में से एक है और लगभग 20% डिज़ाइन इंजीनियरों (उद्योग रिपोर्ट) को प्रदान करता है।

3.8 इसके अलावा , सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने लगभग 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपए के संचयी निवेश के साथ पांच (5) सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है। साथ ही, भारतीय उत्पादों के लिए चिप्स डिजाइन करने के लिए डिजाइन लिंकड प्रोत्साहन योजना के तहत 15 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को भी मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, 41 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को चिप्स डिजाइन करने के लिए आवश्यक उपकरणों (इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) कहा जाता है) तक पहुंच के लिए मंजूरी दी गई है, जिसे सी-डैक बेंगलुरु में चिपइन सेंटर में स्थापित राष्ट्रीय ईडीए टूल ग्रिड द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

3.9 चिप डिजाइन के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए सरकार ने चिप्स टू स्टार्टअप ('सी2एस') कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण (वीएलएसआई) और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन में लगभग 113 प्रतिभागी संस्थानों में 85 हजार विशेषज्ञ कार्यबल को प्रशिक्षित करने की योजना है।
